

Man held for '21 murder of Bengal BJP worker

Press Trust of India

letters@hindustantimes.com

KOLKATA: The CBI on Thursday arrested a proclaimed offender from Siliguri in north Bengal, in a 2021 post-poll violence case relating to the murder of BJP worker Manik Maitra in Cooch Behar's Sitalkuchi, the agency said in a statement.

The accused, Shyamal Barman, was at large since registration of FIR in the case and never joined the investigation or the trial, the CBI claimed.

The agency had announced a cash reward of ₹50,000 for his arrest, it said.

Barman was produced in court and remanded in judicial custody, the CBI added.

Maitra, a BJP worker from Sitalkuchi, was attacked by unknown persons who assaulted him with an iron rod after the assembly election results were declared on May 2, 2021.

According to the FIR, he was also shot by the attackers. The victim was later taken to a local hospital, where he died the next day.

The matter was first heard by a bench of the Calcutta High Court which took cognisance of a report by the National Human Rights Commission (NHRC) in this regard.

The CBI, at the direction of the high court, took over the investigation into Maitra's death and filed an FIR on August 27 that year.

AP cop faces fresh scrutiny over 'suicide video' of goon

Venu.Lanka@timesofindia.com

Vijayawada: Even as controversy brews over the alleged custodial death of history-sheeter Sai Krishna, Krishnalanka police inspector Nagaraju, who has since been suspended, is facing fresh allegations in connection with the suicide of another history-sheeter, Perupogu Kranthi Kumar.

Kranthi Kumar, son of MRPS activist Perupogu Venkateswara Rao Madiga, died by suicide on May 21. Weeks later, the case has resurfaced dramatically following the emergence of a selfie video purportedly recorded by Kranthi before his death. The video went viral on social media on Thursday.

In the purported video, Kranthi Kumar alleged that he was being harassed and assaulted by Nagaraju. He

History-sheeter missing case: AP court orders cops to preserve CCTV footage

Vijayawada: The missing case of Vijayawada history-sheeter Gade Sai Krishna took a significant turn on Thursday after II additional judicial magistrate of first class court directed authorities to preserve all CCTV footage recorded at Krishnalanka police station between May 1 and June 1. Acting on petitions filed by Sai Krishna's mother, Gade Vijayalakshmi, the court ordered police officials to protect and store footage from cameras installed in and around the police station. The court also ordered the production of call data records and location details of two mobile numbers of Sai Krishna between May 1 and June 1. TNN

accused the officer for driving him to suicide. The contents of the video have sparked fresh debate, particularly because the allegations target the same officer, who is already facing scrutiny in Sai Krishna case.

Police sources pointed out that Kranthi Kumar had a criminal history, with nine cases registered against him

in various police stations in and around Vijayawada.

Meanwhile, former Vijayawada MP Kesineni Srinivas (Nani) on Thursday approached the National Human Rights Commission, seeking accountability from senior officers. He also demanded the suspension of NTR district police commissioner SV Rajasekhar Babu.

Custodial death: Ex-MP moves NHRC for probe

DC CORRESPONDENT
VIJAYAWADA, JUNE 18

Former MP Kesineni Srinivas lodged a complaint with National Human Rights Commission (NHRC) on the custodial death of Gade Sai Krishna of Krishnalanka and cremation of his body in a clandestine manner.

The former MP went on to demand a judicial inquiry and suspension of the Vijayawada police commissioner. In his complaint, Kesineni stated that the local youth Sai Krishna had been taken into custody by Krishnalanka police on May 9 from Markapuram on charges of his involvement in criminal cases.

He had been detained for over 35 days at various locations and inside the Krishnalanka police station, where he had been subject to third-degree torture, which led to his death.

The family of the deceased has accused the police of cremating Sai Krishna's body and dumping his ashes into the Krishna River.

The ex-MP requested the NHRC to order an independent judicial inquiry into the illegal detention, brutal torture, custodial death and illegal disposal of the body and ashes of Sai Krishna.

समस्तीपुर में नौकरी के नाम पर बंधक बनाए गए 105 लड़के-लड़कियां मुक्त

समस्तीपुर, निज प्रतिनिधि। समस्तीपुर में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लड़के-लड़कियों को बंधक बनाने और उनसे ठगी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है।

इस गिरोह के चंगुल में फंसे 105 लड़के-लड़कियों को पुलिस ने मुफरिसल थाना क्षेत्र के मुसापुर और धर्मपुर मोहल्ले के दस अलग-अलग ठिकानों से मुक्त कराया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर यह अभियान बुधवार की आधी रात से गुरुवार की सुबह सात बजे तक चला। मुक्त कराये गये पीड़ितों में 67 लड़के और 38 युवतियां हैं। उनमें 46



गुरुवार को समस्तीपुर के मुफरिसल थाने में कतार में खड़ा कर किया जा रहा मुक्त कराये गए लड़के-लड़कियों का सत्यापन।

नाबालिग भी हैं। पुलिस ने गिरोह से जुड़ी तीन महिलाओं समेत नौ आरोपितों को हिरासत में लिया है। हालांकि गिरोह का सरगना आर्यन मौके

से फरार हो गया। मुक्त कराये गए पीड़ितों में से अधिकतर असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के हैं।

गेलवे प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर चल रहा था पूरा रैकेट, पीड़ितों से चेन मार्केटिंग के जरिए नए लोगों को जोड़ने का बनाया जाता था दबाव नौकरी का झांसा दे 105 लड़के-लड़कियों को बनाया था बंधक

समस्तीपुर

समस्तीपुर, निज प्रतिनिधि। समस्तीपुर में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लड़के-लड़कियों को बंधक बनाने और उनसे ठगी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। गेलवे प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के चंगुल में फंसे 105 लड़के-लड़कियों को पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धरमपुर और मुसापुर स्थित दस अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर मुक्त कराया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल पर यह अभियान बुधवार की आधी रात से गुरुवार की सुबह सात बजे तक चला। मुक्त कराये गये पीड़ितों में 67 लड़के और 38 युवतियां हैं। उनमें 39 नाबालिग हैं। पुलिस ने तीन महिलाओं समेत नौ आरोपितों को हिरासत में लिया है। हालांकि, सरगना आर्यन फरार हो गया।

पुलिस के मुताबिक, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों के लड़के-लड़कियों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। उनसे मोटी रकम वसूलकर उनके प्रमाण-पत्र और मोबाइल जन्त कर लिये गये थे। पीड़ितों में ज्यादातर भूटान सीमा से सटे असम



10
ठिकानों पर सात घंटे तक छापेमारी मानवाधिकार आयोग की पहल पर

गुरुवार को मुफस्सिल थाने पर कतार में खड़े कर लड़के-लड़कियों को किया जा रहा सत्यापन। • हिन्दुस्तान

- मुक्त कराए गए लोगों में 67 लड़के और 38 लड़कियां, इनमें 39 नाबालिग भी शामिल
- पुलिस ने तीन महिलाएं समेत नौ संदिग्धों को हिरासत में लेकर शुरु की पूछताछ

पीड़ितों से 25-25 हजार रुपये वसूले थे

सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन देकर युवाओं को बुलाया जाता था। पीड़ितों का कहना है कि उनसे 25-25 हजार रुपये लेकर ट्रेनिंग किट के नाम पर कॉस्मेटिक और सामान्य उपयोग का सामान दिया जाता था, जिसकी बाजार में कीमत महज एक से डेढ़ हजार रुपये है। कंपनी से जुड़े लोग युवक-युवतियों को चेन मार्केटिंग के जरिए कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने के काम में लगा देते थे। उन्हें नए-नए ग्राहक बनाने होते थे। इसके बदले कमीशन का लालच दिया जाता था।

के तामुलपुर, मंगलदोई, भैरवकुंड, उदालगुड़ी, तिनसुकिया और दिमाकुची के निवासी हैं। एएसपी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि मानव तस्करी, अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने, घोखाघड़ी और ठगी समेत अन्य

आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रेस्क्यू अभियान में छह थानों की पुलिस और करीब 150 से अधिक जवान शामिल रहे। एएसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी मुफस्सिल थाना पहुंचकर पीड़ितों से

पूछताछ की। आर्यन और अन्य की गिरफ्तारी को एसआईटी बनाई गई है।
दस अलग-अलग कमरों में रखा था: गेलवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाये गये लड़के-लड़कियों को

असम की लड़की ने साझा किया लोकेशन तो पता चला

गिरोह का भंडाफोड़ असम की पीड़िता रेणु (काव्यनिक नाम) की सुझाव से हुआ। वह एक दोस्त के बुलाने पर समस्तीपुर आई थी। रेणु ने चुपके से बहन से व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन शेयर कर दिया। बहन ने पुलिस से मदद नहीं मिला तो मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचाया।

24 घंटे निगरानी रखी जाती थी, मारते भी थे

पीड़ितों का कहना है कि उन पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी। रात में कमरों को बाहर से बंद कर दिया जाता था। घर जाने या नौकरी छोड़ने की बात करने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी तथा धमकियां दी जाती थीं। असम निवासी रवि ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवती ने उससे संपर्क किया था। उसने खुद को सरकारी कार्यालय में कार्यरत बताते हुए उसे भी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया।

किराये के दस अलग-अलग कमरों में रखा गया था। यहीं पर उनके भोजन के लिए मेस भी चलता था। कमरों को फिलहाल सील कर दिया गया है। आशंका है कि इस गिरोह ने करीब 300 लड़के-लड़कियों को अपने जाल में

गिरफ्तार पांच आरोपित जेल भेजे गए, चार संदिग्धों से हो रही पूछताछ

समस्तीपुर (निज)। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं को बंधक बनाकर रखने और उनसे नेटवर्क मार्केटिंग का काम कराने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सभी को जेल भेज दिया गया है। चार अन्य संदिग्धों से अब भी मुफस्सिल थाने में पूछताछ जारी है। इस संबंध में मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गेलवे) के संचालक समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों में दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र की शाखा कुमारी, गया जिले के कोच थाना क्षेत्र के बैकटपुर निवासी प्रमोद ठाकुर, असम के तामुलपुर जिले की अंजुलियस ओरंग व नवगांव जिले की

छापे के दौरान महिला पुलिसकर्मी पर हमला

मुसापुर में छापेमारी के दौरान गिरोह से जुड़ी एक महिला ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे एक महिला पुलिस के सिर में गंभीर चोट आई। उनका इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का मुख्य संचालक और हेड बॉस आर्यन नामक युवक है, जिसे सभी सर कहकर बुलाते थे। छापेमारी के दौरान मची अफरातफरी और अंधेरे का फायदा उठाकर आर्यन समेत कई आरोपी फरार हो गए।

पोलो उरांव तथा लखीमपुर जिले के नॉर्थ लखीमपुर थाना क्षेत्र के कुहीडोंगा निवासी किटब उरांव के पुत्र पोलो उरांव शामिल हैं।

फंसा रखा था।

मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने 'उम्मीदवार' बन की थी रेकी : गिरोह तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य विकास सिंह ने रेकी दो दिन पहले रेकी

की थी। वह नौकरी के इच्छुक युवक बनकर समस्तीपुर पहुंचे और कालिका कॉम्प्लेक्स, मुसापुर और धरमपुर के ठिकानों का दौरा किया। संचालकों ने उन्हें भी नौकरी का झांसा देकर 25 हजार रुपये जमा करने को कहा।

मानवाधिकार आयोग से शिकायत करेगा एचआरयूएफ

पटना. ह्यूमन राइट्स अम्ब्रला फाउंडेशन (एचआरयूएफ) के संस्थापक अध्यक्ष विशाल रंजन दफ्तुआर ने भरत भूषण तिवारी के पुलिस एनकाउंटर को गंभीर मानवाधिकार हनन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को कठोर दंड दिलाने के लिए एचआरयूएफ विशेष पहल करेगा. दफ्तुआर ने कहा कि संस्था इस मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष उठायेगी व विस्तृत शिकायत पत्र भेजेगी. दफ्तुआर ने आरोप लगाया कि आत्मसमर्पण के बाद भी उन्हें गोली मारी गयी. एचआरयूएफ ने निष्पक्ष जांच की मांग की है.



Source: <https://pragativadi.com/odisha-cm-suspends-senior-ips-officer-dayal-gangwar-amid-baliana-lynching-controversy/>

Odisha CM Suspends Senior IPS Officer Dayal Gangwar Amid Baliana Lynching Controversy
by Yajati Rout June 18, 2026 in Odisha, Trending Now

In a decisive administrative move, Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has ordered the transfer of senior IPS officer Dayal Gangwar, Officer on Special Duty (OSD) in the Home Department, with immediate effect.

The decision comes in the wake of intense public scrutiny and allegations linking Gangwar, a 1998-batch officer, to the tragic mob-lynching of Government Railway Police (GRP) Constable Soumya Ranjan Swain on May 7 in Baliana, on the outskirts of Bhubaneswar.

Swain's family has accused the senior officer of mentally and physically harassing the constable by allegedly forcing him to perform personal duties unrelated to his official role during Gangwar's earlier tenure as ADG (Railway).

As the Crime Branch continues its probe and the National Human Rights Commission (NHRC) has recorded statements, all eyes remain on whether further action will follow.

CM Majhi's government has signalled zero tolerance for any lapses that erode public confidence in the system. Justice for Soumya and systemic reforms could define the legacy of this sensitive case.



Source: <https://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2026/Jun/19/east-godavari-sp-begins-probe-into-sai-krishnas-disappearance>

Andhra Pradesh

East Godavari SP begins probe into Sai Krishna's disappearance

The rowdy-sheeter case has gained significant attention following allegations of custodial torture and a suspected lockup death at the Krishna Lanka police station.

Phanindra Papasani Updated on: 19 Jun 2026, 8:16 am

VIJAYAWADA: East Godavari district Superintendent of Police D Narasimha Kishore has been appointed as investigation officer to conduct an independent probe into the circumstances surrounding Gade Sai Krishna's disappearance. The disappearance of Sai Krishna, a rowdy-sheeter, after he was allegedly taken into custody by Krishna Lanka police has triggered statewide concern, prompting the State government to order a high-level inquiry.

The rowdy-sheeter case has gained significant attention following allegations of custodial torture and a suspected lockup death at the Krishna Lanka police station.

According to sources, Narasimha Kishore, along with senior officers, visited the Krishna Lanka police station on Thursday, and examined available records and evidence.

More torture claims surface against CI

Krishna Lanka Circle Inspector SSV Nagaraju has already been suspended pending investigation. Murali Krishna has assumed charge as the new Circle Inspector.

Sai Krishna's mother Vijayalakshmi has made an emotional appeal to authorities, demanding that police reveal her son's whereabouts. "Show us where Sai Krishna is. If he is dead, at least hand over his body," she said. Family members have demanded a Central Bureau of Investigation (CBI) inquiry, alleging attempts to suppress evidence in the case.

Taking the issue to national level, former Vijayawada MP Kesineni Srinivas alias Nani has written to the National Human Rights Commission, alleging a custodial death and accusing police officials of destroying evidence. The former MP further argued that senior police officers should be held accountable under the principle of command responsibility.

Adding to the controversy, purported videos surfaced online in which individuals alleged that suspended CI Nagaraju subjected them to physical torture. A video linked to the suicide of Kranthi Kumar, who died last month, reportedly accused Nagaraju of harassment. One Mahankali Chandu has also claimed to be an eyewitness, alleging that Sai Krishna was brutally assaulted inside the police station.

Vijayawada police have so far not issued a statement, while the probe continues amid growing public scrutiny.

However, the appointment of an SP rank officer instead of an officer above the rank of IG to probe the matter, has become a subject of discussion among IPS circles.

Source: <https://www.msn.com/en-in/news/india/stakeholders-support-legislation-to-decriminalise-politics-joint-committee-chairperson-sarangi/ar-AA25Skza?uxmode=ruby>

Stakeholders support legislation to decriminalise politics: Joint committee chairperson Sarangi

Story by PTI

18 Jun • 2 min read • Updated 1d ago

Key takeaways

Legislative Support: The Constitution (130th Amendment) Bill, 2025 aims to decriminalise politics, prevent government from being run from jail, and strengthen accountability**. Stakeholders, including states like Telangana and Punjab, have expressed support with suggestions for modifications.

Key Provisions: If a PM, CM, or minister is arrested for an offence with punishment of 5+ years and not granted bail within 30 days, they would cease to hold office**, reinforcing public trust and accountability.

Stakeholder Engagement: The 31-member joint committee held meetings with state officials, NHRC, NGOs, and universities across 9 states/UTs, receiving supportive feedback** and recommendations without opposition to the bill's intent.

New Delhi, Jun 17 (PTI) The joint committee of Parliament examining the Constitution (130th Amendment) Bill, 2025, on removal of PMs, CMs and ministers from office if they are detained for over 30 days on serious charges has received support and suggestions on the proposed legislation and found no resistance to its intent to decriminalise politics, panel chairman and BJP MP Aparajita Sarangi said on Wednesday.

The 31-member committee held a stakeholders' meet at the Delhi Secretariat with Chief Minister Rekha Gupta, departments of Law and Home of the Delhi government, National Human Rights Commission (NHRC), Guru Gobind Singh Indraprastha University and NGO Common Cause.

Addressing a press conference, Sarangi said that the stakeholders extended support to the bill and also submitted some written comments and suggestions.

Sarangi said the committee has held 11 meetings so far and visited nine states and Union Territories, including Rajasthan, Haryana, Delhi, Chhattisgarh, Telangana and Punjab.

She claimed that states such as Telangana and Punjab, which are ruled by non-NDA parties, are among those who have expressed support for the spirit of the proposed legislation while suggesting certain modifications.

The proposed legislations seeks to decriminalise politics, prevent government being run from jail and strengthen accountability in public life, she said.

The Constitution (130th Amendment) Bill and two related legislations -- J-K Reorganisation (A) Bill, 2025, and The Government of UTs (A) Bill, 2025 -- were tabled in the Lok Sabha on August 20, 2025.

One of the key provisions in the Constitution (130th Amendment) Bill proposes that if the prime minister, a chief

minister, a Union minister or a state minister is arrested for an offence carrying a punishment of five years or more and is not granted bail within 30 days, the person would cease to hold office.

The joint committee was constituted in November 2025 to examine the Bills.

Sarangi said the panel's interactions so far have indicated support rather than resistance to the intent of the bills introduced in the Lok Sabha in August 2025.

"There have been useful suggestions and recommendations, but no opposition to the objective behind them," she said.

The panel, which has been boycotted by the opposition, also met Delhi Chief Minister Rekha Gupta who lauded the bills as an important initiative to reinforce accountability in public life.

She welcomed the chairperson and members, including K Laxman, Ujjwal Nikam, DK Aruna, Parshottam Rupala, Asaduddin Owaisi, Anurag Thakur, Brij Lal, Brijmohan Agrawal among others, at the Secretariat.

"The proposed bills represent an important initiative towards reinforcing accountability, transparency and constitutional morality in public life," she said.

The primary objective of the Constitution (130th Amendment) Bill, currently under consideration, is to further strengthen public trust in individuals holding public office, she said. PTI VIT RT

Source: <https://odishabarta.com/lynching-controversyips-dayal-gangwar-suspended-by-chief-ministerodisha/>

Lynching Controversy;IPS Dayal Gangwar Suspended by Chief Minister,Odisha
□ odishabarta □ June 19, 2026

Bureau,Odishabarta

Bhubaneswar,(18/06/26):In a decisive administrative move, Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has ordered the transfer of senior IPS officer Dayal Gangwar, Officer on Special Duty (OSD) in the Home Department, with immediate effect.

The decision comes in the wake of intense public scrutiny and allegations linking Gangwar, a 1998-batch officer, to the tragic mob-lynching of Government Railway Police (GRP) Constable Soumya Ranjan Swain on May 7 in Baliana, on the outskirts of Bhubaneswar.

Swain's family has accused the senior officer of mentally and physically harassing the constable by allegedly forcing him to perform personal duties unrelated to his official role during Gangwar's earlier tenure as ADG (Railway).

As the Crime Branch continues its probe and the National Human Rights Commission (NHRC) has recorded statements, all eyes remain on whether further action will follow.

CM Majhi's government has signalled zero tolerance for any lapses that erode public confidence in the system. Justice for Soumya and systemic reforms could define the legacy of this sensitive case.



Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/odisha-ips-officer-suspended/amp_articleshow/131838441.cms

Odisha IPS officer suspended

City | Debabrata Mohapatra | Jun 18, 2026, 23:16 IST

Bhubaneswar: Odisha govt on Thursday suspended senior IPS officer Dayal Gangwar, who has been at the centre of a controversy following last month's Baliana lynching case involving railway constable Soumya Ranjan Swain.

"Chief minister Mohan Charan Majhi has suspended Dayal Gangwar," a brief statement from the CMO read, without elaborating on the grounds for action.

Govt sources said Gangwar's role is not directly linked to the lynching, but he faces an administrative inquiry after Swain's family accused him of harassment and exploitation. The family claims Swain was compelled to serve as Gangwar's domestic help during his tenure as ADG (railway) in 2023-24.

As per the suspension order, seen by TOI, "The DGP submitted a confidential report regarding retention of eight govt railway police personnel by Dayal Gangwar for work in his residence, even after his transfer from the post of ADGP railway & coastal security, without approval of the competent authority. A disciplinary proceeding against Gangwar is contemplated on the grounds of grave misconduct as a member of the Indian Police Service."

Gangwar's suspension comes days after the National Human Rights Commission (NHRC) questioned him during its probe earlier this month into Swain's murder and misuse of his post. Gangwar had earlier been shunted from the post of ADG (communication) and assigned as officer on special duty (OSD) in the home department on May 25 — a posting widely seen as punitive and insignificant.

The govt railway police (GRP) recently submitted a report to the Human Rights Protection Cell (HRPC) of Odisha police, alleging that Swain was illegally engaged for Gangwar's domestic work.

Swain, 32, was lynched by a mob on May 7 after allegations surfaced that he attempted to rape a 22-year-old woman on the roadside. The incident unfolded in front of police personnel, prompting the suspension of four officers and the transfer of the Baliana inspector in-charge. So far, 18 people have been arrested.

Source: <https://www.msn.com/en-in/news/India/nhrc-steps-in-as-children-trek-14-km-through-forest-in-karnataka/ar-AA25Sfm8>

NHRC steps in as children trek 14 km through forest in Karnataka

1d • 2 min read

Bengaluru: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued conditional summons to senior Karnataka government officials over allegations that more than 50 students from a remote village in Chamarajanagar district are forced to walk nearly 14 kilometres daily through dense forest and wildlife-prone areas to attend school.

The summons, issued through a speaking order dated June 16, have been served to the Principal Secretary of the Department of Primary and Secondary Education and the Deputy Commissioner of Chamarajanagar district.

The case relates to students from Pachedoddi village in Hanur taluk, who reportedly traverse forest stretches, including areas known for tiger movement, due to the absence of proper road connectivity and public transport facilities.

The matter came before the NHRC following a pro bono complaint filed by Hyderabad-based human rights advocate Yennam Balachander Reddy. The complaint alleged that the students are exposed to serious risks, including wild animal attacks, physical exhaustion, psychological stress and disruption of education, thereby affecting their constitutional rights to life, safety, dignity and education.

No toilets, tribal kids brave snakes in forest: NHRC asks Telangana to explain Details not furnished despite repeated directions

According to NHRC records, the commission had on December 23, 2025, directed the Karnataka Education Department and the district administration to conduct an inquiry and submit an action taken report (ATR) within two weeks. A reminder was subsequently issued on February 3, 2026. However, despite repeated directions, the authorities allegedly failed to furnish the required report.

Taking serious note of the non-compliance, the NHRC observed that if the allegations are found to be true, they may amount to violations of fundamental rights guaranteed under Articles 21 and 21A of the Constitution.

The Commission also referred to a 2017 Supreme Court judgment in *Manager Palathingal MLP School vs Sethumadhavan PK*, which emphasised that children should not be compelled to walk long distances to access education.

The conditional summons have been issued under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The officials have been directed to appear personally or through an authorised representative familiar with the facts of the case.

The matter is scheduled for hearing before the NHRC on July 15 at Manav Adhikar Bhawan in New Delhi. However, the commission has clarified that the personal appearance of the officials will not be required if the inquiry report and ATR are submitted on or before July 1.

The case has once again brought attention to the challenges faced by students in remote forest regions and the need for improved connectivity and educational access in rural Karnataka.

Source: <https://dy365live.com/northeast/nhrc-urged-to-probe-alleged-extortion-linked-to-complaint-in-minor-chakma-girl-death-case-12051101>

NorthEast

NHRC Urged to Probe Alleged Extortion Linked to Complaint in Minor Chakma Girl Death Case

The case relates to the death of a minor Chakma girl who was reportedly employed as a domestic worker and died in Roing, Lower Dibang Valley district, on December 11, 2025

DY365 Jun 18, 2026 16:20 IST

Guwahati/New Delhi: The Arunachal Pradesh Chakma Youth Association (APCYA) has approached the National Human Rights Commission (NHRC), seeking an investigation into allegations of extortion linked to a complaint concerning the death of a 15-year-old Chakma girl in Arunachal Pradesh.

The case relates to the death of a minor Chakma girl who was reportedly employed as a domestic worker and died in Roing, Lower Dibang Valley district, on December 11, 2025. Earlier, the NHRC, through proceedings dated March 13, 2026, had recommended that the Government of Arunachal Pradesh hand over the inquiry to the Central Bureau of Investigation (CBI), citing the need for a fair, independent and child-sensitive investigation into the matter.

In a fresh complaint submitted to the NHRC, APCYA alleged that Chikond Chand Chakma of the All India Chakma Students Union (AICSU), who had originally filed the complaint before the NHRC, along with another individual identified as Amit Chakma, received or extorted ₹3 lakh from the employer of the deceased minor to settle the matter.

The allegation is based on a video that surfaced on social media in which the victim's father, Lakkhimuni Chakma of Gautampur village in Changlang district, allegedly claimed that the employer paid ₹3 lakh, of which he received ₹1.10 lakh while the remaining ₹1.90 lakh was allegedly taken by the two individuals.

APCYA further alleged that after the video surfaced, AICSU constituted an internal inquiry committee to examine the matter. According to the association, the committee subsequently dismissed the allegations made by the victim's father.

Reacting to the development, APCYA president Rup Singh Chakma claimed that if the allegations are found to be true, it would amount to a serious misuse of a human rights complaint process and could potentially affect the pursuit of justice in the death case.

The organisation has requested the NHRC to direct its Investigation Division to conduct an independent inquiry into the allegations. APCYA has also sought referral of the findings to the CBI, contending that any alleged monetary transaction connected to the case could interfere with the ongoing pursuit of justice.

There has been no immediate response from AICSU regarding the fresh complaint filed before the NHRC. The

allegations have not been independently verified, and no findings have been issued by the NHRC on the latest claims.



Source: <https://www.thehansindia.com/andhra-pradesh/custodial-death-of-youth-alleged-1087789>

Custodial death of youth alleged

Created On: 19 June 2026 6:45 AM IST

By The Hans India

Rajamahendravaram: Human Rights Watch Director Balu Akkisa has lodged a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC), New Delhi, seeking an inquiry into the alleged custodial death of a youth in Krishna Lanka Police Station, Vijayawada. The complaint has been registered by the NHRC as Diary No 13905/IN/2026. According to the complaint, G Sai Krishna, a 25-year-old youth against whom criminal cases had reportedly been registered in the past, was taken into police custody on May 9, 2026, as part of an investigation. However, he has not returned home since then and has reportedly been missing for more than a month. The complaint cites reports published in print and electronic media suggesting that Sai Krishna's death may have occurred while he was in police custody. His mother has alleged that her son may have been subjected to torture during detention in Vijayawada and suspects that he died as a result of custodial violence. Balu Akkisa urged the NHRC to conduct an independent and impartial investigation into the incident, determine the facts surrounding Sai Krishna's disappearance and suspected death, and ensure accountability if any human rights violations are established. The complaint further demands that appropriate compensation be provided to the victim's family and that justice be delivered in accordance with the law. The case has drawn attention from human rights activists, who have called for transparency and a thorough probe into the circumstances surrounding the youth's disappearance and alleged custodial death.

Source: <https://nenews.in/aranachal-pradesh/aranachal-pradesh-chakma-body-seeks-nhrc-inquiry-into-alleged-extortion-linked-to-minor-chakma-girls-death/54543/>

Arunachal Pradesh Chakma body seeks NHRC inquiry into alleged extortion linked to minor Chakma girl's death
Northeast NewsbyNortheast News June 18, 2026 in Arunachal Pradesh

Itanagar: The Arunachal Pradesh Chakma Youth Association (APCYA) has approached the National Human Rights Commission (NHRC), seeking an investigation into allegations that money was taken from the employer of a 15-year-old Chakma girl who died in Arunachal Pradesh, even as the Commission has already ordered a CBI inquiry into the case.

In a statement issued on Thursday, the APCYA said it had filed a complaint before the NHRC alleging that Chikond Chand Chakma of the All India Chakma Students Union (AICSU), who is the complainant in NHRC Case No. 57/2/18/2025-CL, and another individual, Amit Chakma, allegedly received or extorted Rs 3 lakh from the girl's employer to settle the matter.

The NHRC had earlier, through its order dated March 13, 2026, recommended that the Arunachal Pradesh government hand over the investigation into the death of the minor girl to the Central Bureau of Investigation (CBI).

The Commission cited lapses in the earlier inquiries and called for a fair, independent and child-sensitive investigation under relevant criminal and child protection laws.

The girl, who was employed as a domestic worker, died in Roing in Lower Dibang Valley district on December 11, 2025.

According to the APCYA, a video circulated on social media in which the victim's father, Lakkhimuni Chakma of Gautampur village in Changlang district, alleged that the employer had paid Rs 3 lakh. He claimed that he received Rs 1.10 lakh, while the remaining Rs 1.90 lakh was allegedly taken by Chikond Chand Chakma and Amit Chakma.

APCYA president Rup Singh Chakma alleged that after the video surfaced, the AICSU constituted an internal inquiry committee instead of bringing the matter to the notice of the NHRC. He claimed that the committee, comprising office-bearers and members of the student organisation and its affiliated bodies, later rejected the allegations made by the victim's father.

Describing the matter as serious, Rup Singh Chakma alleged that the reported monetary transaction could undermine the investigation into the girl's death and deny justice to the victim and her family.

"This is not only a grave injustice in a case involving the death of a 15-year-old girl, for which the NHRC had ordered a CBI inquiry, but it also raises concerns that the complaint filed before the Commission may have been used as a means to extract money, compromise the investigation, and deny justice to the victim and her family," Chakma said.

He further claimed that complaints filed before the NHRC should not be misused as a means of extracting money or settling disputes. "The alleged misuse of the NHRC to extort money or settle a case involving the death of a young girl calls for urgent intervention by the Commission. The NHRC must ensure that its platform is not used for personal gain," he added.

"Extortion from employers of child labourers and from victims' families during rescue operations has become a growing menace among the Chakma community in Arunachal Pradesh. Such practices often prevent legal action against the accused and contribute to the continuation of child labour from the Chakma community in the state," he stated.

The Arunachal Pradesh Chakma Youth Association (APCYA) has urged the NHRC to direct its Investigation Division to probe the allegations, stating that the credibility of the Commission is at stake.

It has also requested that its complaint, along with the findings of any NHRC inquiry, be forwarded to the CBI, arguing that the alleged exchange of Rs 3 lakh could compromise the investigation and hinder justice in the case of the 15-year-old Chakma girl's death.

Source: <https://nenow.in/north-east-news/aranachal-pradesh/aranachal-apcya-seeks-nhrc-probe-into-extortion-claims-over-minor-girls-death.html>

Arunachal: APCYA seeks NHRC probe into extortion claims over minor girl's death

The case relates to the death of a 15-year-old Chakma girl who was employed as a domestic help and died in Roing on December 11, 2025

by Sandeep Sharma

June 18, 2026 8: 45 pm

Reported by Sandeep Sharma

Guwahati: The Arunachal Pradesh Chakma Youth Association (APCYA) has approached the National Human Rights Commission (NHRC), seeking an investigation into allegations that Rs 3 lakh was allegedly taken from the employer of a 15-year-old Chakma girl who died in Roing, Lower Dibang Valley district, while the case was under consideration by the rights body.

In a complaint submitted to the NHRC on Thursday, the APCYA urged the commission to register a case against Chikond Chand Chakma of the All India Chakma Students Union (AICSU), who is the complainant in NHRC Case No. 57/2/18/2025-CL, and his alleged accomplice Amit Chakma.

The association alleged that the two took or extorted Rs 3,00,000 from the employer of the deceased girl in an attempt to settle the matter.

The case relates to the death of a 15-year-old Chakma girl who was employed as a domestic help and died in Roing on December 11, 2025.

Earlier, on March 13, 2026, the NHRC had recommended that the Chief Secretary of Arunachal Pradesh hand over the inquiry into the girl's death to the Central Bureau of Investigation (CBI) for a "fair, independent, and child-sensitive" investigation, citing lapses in the earlier inquiries conducted in the case.

According to the APCYA, a video of the victim's father, Lakkhimuni Chakma of Gautampur village under Diyun Circle in Changlang district, later surfaced on social media.

In the video, he allegedly stated that the employer had paid Rs 3 lakh, of which he received Rs 1.10 lakh, while the remaining Rs 1.90 lakh was taken by Chikond Chand Chakma and Amit Chakma.

APCYA president Rup Singh Chakma alleged that after the video emerged, the AICSU constituted an internal inquiry committee instead of informing the NHRC about the allegations.

The committee comprised Drishyamuni Chakma, president of AICSU; Uttam Chakma, adviser, AICSU; Parbesh Chakma, president of the Central Mizoram Chakma Students Union and executive member of AICSU; Ahimsak Chakma, general secretary of AICSU; Jiban Basu Chakma, president of the Tripura Chakma Students Association and member of AICSU; and Sunil Kumar Chakma, legal secretary of AICSU.

“Expectedly, the AICSU, which acted as the judge and jury with respect to the complaint against itself, dismissed the allegations made in the video by Lakkhimuni Chakma, father of the deceased,” Rup Singh Chakma said.

He further alleged that the matter raised serious concerns about the integrity of the complaint process and its possible impact on the pursuit of justice in the case.

“This is not only gross injustice against the death of a 15-year-old girl, in which the NHRC was pleased to order an inquiry by the CBI, but it appears to be a case of the complaint filed with the NHRC being used as a means to extort money to settle the matter, vitiate the investigation, and deny justice to the victim and her family,” he said.

Rup Singh Chakma also claimed that misuse of complaints relating to child labour cases had become a growing concern within sections of the Chakma community in Arunachal Pradesh.

“This abuse of the NHRC for the purpose of extortion or taking money to settle the death of a girl calls for proper intervention by the NHRC to ensure that no one uses the NHRC for the purpose of extortion. Extortion from those who employ child labourers from the Chakma community and the victims’ families to settle the matters, especially during rescue of the victims, has become a menace among the Chakmas in Arunachal Pradesh. Often the accused cannot be prosecuted, thereby creating a vicious cycle of child labour from the Chakma community in the state,” he alleged.

The APCYA has requested the NHRC to direct its Investigation Division to conduct an inquiry into the allegations and to share its findings with the CBI, contending that the alleged exchange of Rs 3 lakh could potentially affect the ongoing inquiry and the course of justice in the death of the minor girl.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-seeks-report-on-police-shortage-in-jeypore/amp_articleshow/131832309.cms

NHRC seeks report on 'police shortage' in Jeypore
City Lalmohan Patnaik | Jun 18, 2026, 18:52 IST

Cuttack: National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday asked the Odisha govt to examine the allegations of acute police manpower shortage and inadequate infrastructure at Jeypore town in Koraput district and submit an action-taken report within eight weeks.

The direction came after the commission considered a complaint filed by Jeypore-based human rights activist and advocate Anup Kumar Patro. In a communication issued on June 18 to the chief secretary, the NHRC said the complaint was being forwarded to the competent authority for appropriate action.

"The authority concerned is directed to take appropriate action within eight weeks, associating the complainant/victim, and to inform him/her of the action taken in the matter," the commission stated.

Patro's complaint highlighted what it described as a persistent shortage of police personnel in Jeypore Town, Jeypore Sadar and Women police stations. Referring to Bureau of Police Research and Development (BPRD) data, he claimed Odisha's police-to-population ratio (between 80 and 133 personnel per lakh) remains below the national average and the United Nations-recommended benchmark of 222 per one lakh.

According to the petition, the shortage of personnel and lack of modern infrastructure have implications not only for policing but also for human rights. It alleged that inadequate housing facilities, poor living conditions and excessive workload affect the dignity and welfare of police personnel, while insufficient investigative resources compromise citizens' access to effective and timely investigation.

The complaint further contended that inadequate police strength in Jeypore, a major urban centre of Koraput district, has left residents vulnerable to crime and weakened delivery of policing services. It also alleged that the state failed to establish adequate welfare mechanisms and improve working conditions in line with Supreme Court directives on police reforms.

Seeking intervention, Patro urged the NHRC to direct the chief secretary and director general of police to furnish details of sanctioned and actual manpower in the three police stations, take steps to fill vacancies and conduct an inquiry into police housing and infrastructure across Koraput district.

Source: <https://www.etvbharat.com/en/state/aranachal-pradesh-minor-worker-death-case-takes-new-turn-youth-body-alleges-extortion-seeks-nhrc-probe-enn26061804486>

ETV Bharat / state

Arunachal Pradesh Minor Worker's Death Case Takes New Turn: Youth Body Alleges Extortion, Seeks NHRC Probe

Allegations emerge months after NHRC recommended a CBI inquiry into the Arunachal Pradesh teenager's death, reports ETV Bharat's Gautam Debroy.

By ETV Bharat English Team

Published : June 18, 2026 at 5:36 PM IST

New Delhi: The death of a 15-year-old Chakma girl employed as a domestic worker in Arunachal Pradesh has taken a dramatic new turn, with a youth organisation alleging that money meant to settle the matter was siphoned off by individuals associated with the complaint that was originally filed before the National Human Rights Commission (NHRC).

The Arunachal Pradesh Chakma Youth Association (APCYA) on Thursday approached the NHRC seeking an investigation into allegations that Rs 3 lakh was collected from the employer of the girl, who died at Roing in Lower Dibang Valley district of Arunachal Pradesh on December 11, 2025.

The organisation has urged the Commission to examine whether the complaint was misused for personal gain.

The case drew national attention after the NHRC, citing lapses in the initial inquiry, recommended Arunachal Pradesh government in March 2026 to hand over the investigation to the Central Bureau of Investigation (CBI) for a fair, independent and child-sensitive probe into the circumstances surrounding the teenager's death.

Now, APCYA claims that a video circulating on social media features the victim's father, alleging that the employer paid Rs 3 lakh, of which his family received Rs 1.10 lakh while the remaining Rs 1.90 lakh was allegedly retained by Chikond Chand Chakma of the All India Chakma Students Union (AICSU) and another individual, Amit Chakma.

Ironically, the allegations have intensified concerns over whether the pursuit of justice for the deceased may have been compromised by financial dealings outside the legal process.

According to APCYA president Rup Singh Chakma, the AICSU subsequently constituted an internal inquiry committee to examine the allegations and rejected the claims made in the father's video. He argued that such an exercise lacked independence because the organisation was effectively investigating allegations against its own members.

Calling for NHRC intervention, the APCYA alleged that if the claims are true, it could amount to an attempt to influence the course of justice in a case involving the death of a minor domestic worker. The organisation contended that any exchange of money connected with the matter could potentially interfere with the integrity of the investigation and undermine accountability.

Beyond the immediate allegations, the association has raised broader concerns about the vulnerability of children from economically disadvantaged communities who end up in domestic work. It argued that any effort to privately settle such cases could discourage proper prosecution and perpetuate cycles of child labour and exploitation.

The organisation also warned that misuse of human rights mechanisms for alleged extortion, if established, could damage public confidence in institutions designed to protect victims and ensure accountability.

“APCYA has therefore requested the NHRC to initiate an investigation through its own investigation division and, based on its findings, refer the matter to the CBI alongside the already recommended inquiry into the teenager’s death,” Rup Singh Chakma said.



Source: <https://www.deccanchronicle.com/southern-states/andhra-pradesh/ex-mp-kesineni-approaches-nhrc-for-probe-into-sai-krishnas-custodial-death-1964586>

Home » Southern States » Andhra Pradesh

Ex-MP Kesineni Approaches NHRC For Probe Into Sai Krishna's Custodial Death
Sampat G. Samritan 18 June 2026 11:56 PM

The ex-MP went on to demand a judicial inquiry and suspension of the Vijayawada police commissioner.

Vijayawada: Former MP Kesineni Srinivas lodged a complaint with National Human Rights Commission (NHRC) on the custodial death of Gade Sai Krishna and cremation of his body in a clandestine manner. The ex-MP went on to demand a judicial inquiry and suspension of the Vijayawada police commissioner. In his complaint, Kesineni stated that the local youth Sai Krishna had been taken into custody by Krishnalanka police on May 9 from Markapuram on charges of his involvement in criminal cases. He had been detained for over 35 days at various locations and inside the Krishnalanka police station, where he had been subject to third-degree torture, which led to his death. The family of the deceased has accused the police of cremating Sai Krishna's body and dumping his ashes into the Krishna River. The former MP requested the NHRC to order an independent judicial inquiry into the illegal detention, brutal torture, custodial death and illegal disposal of the body as well as ashes of Sai Krishna.

(Source : Deccan Chronicle)

Source: <https://www.amarujala.com/bihar/human-rights-organization-entry-bharat-bhushan-tiwari-encounter-case-bhojpur-police-bihar-police-bihar-news-2026-06-18>

Hindi News > Bihar > Human rights organization entry Bharat Bhushan Tiwari encounter case Bhojpur police Bihar police Bihar news

Bihar : हथियार फेंकने के बाद चार गोलियां क्यों मारीं? पुलिस के पास नहीं है मानवाधिकार आयोग के इस सवाल का जवाब न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: Krishan Ballabh Narayan Updated Thu, 18 Jun 2026 10:44 PM IST

सार

Bihar : भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार संगठन की एंट्री के बाद पुलिस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक युवा जो सिस्टम को सुधारना चाहता था, उसकी इस तरह हुई मौत ने अब कई बड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

विस्तार

भोजपुर के शाहपुर में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का मामला अब और गरमा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को अब सीधे-सीधे मानवाधिकारों का हनन और सरेआम हत्या करार दिया जा रहा है। मशहूर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता और वैश्विक संस्था ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन विशाल रंजन दफ्तुआर ने इस घटना पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह दुनिया की अब तक की सबसे विभत्स मानवाधिकार हनन की घटनाओं में से एक है।

ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन विशाल दफ्तुआर ने इस घटना की तीखी निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। इस मामले को लेकर वे सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखने जा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो पूरा लोकतांत्रिक सिस्टम ही फेल हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग का कहना है कि भरत भूषण तिवारी कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि सिस्टम की खामियों से आक्रोशित एक तेजतर्रार युवा था। उसने कई रचनात्मक कार्यों और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई थी। विशाल दफ्तुआर ने माना कि भरत की कार्यशैली में कुछ कमियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन उसके इरादे नेक थे और वह समाज की भलाई के लिए लड़ रहा था।

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन विशाल दफ्तुआर ने खुद शाहपुर थाना के थानाध्यक्ष से फोन पर बात की। बताया जा रहा है कि पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि जब भरत तिवारी ने पुलिस के आगे अपना हथियार फेंक दिया था, तो फिर उसे एक या दो नहीं... बल्कि चार-चार गोलियां क्यों मारी गईं? पुलिस की तरफ से मिला जवाब बेहद असंतोषजनक था, जो साफ इशारा करता है कि आत्मसमर्पण के बाद भी उसकी जान ली गई।

ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन के चेयरमैन विशाल दफ्तुआर ने इस संबंध में लिखा है कि बिहार पुलिस के चंद लोगों की इस अमानवीयता के चलते पूरा पुलिस फोर्स बदनाम हुआ है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय- राष्ट्रीय मिशनों के दौरान पुलिस की मुस्तैदी को भी मैंने नजदीक से देखा है। अर्धरात्रि में वापसी के दरमियान मेरी सुरक्षा हेतु संबंधित थाना क्षेत्रों की पुलिस को पूरी तरह से मुस्तैद पाया है। लेकिन भोजपुर की इस घटना के लिये दोषी पुलिसकर्मी पुलिस फोर्स के लायक नहीं हैं। चेयरमैन विशाल दफ्तुआर ने आगे कहा कि इसके पूर्व पिछले साल मोतिहारी में वाहन चेंकिंग के दौरान अनुपमा यादव से दुर्व्यवहार मामले में भी मैंने पहल की थी और दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करवाई थी। उन्होंने आगे लिखा है कि मुझे देश की पुलिस पर बेहद गर्व है। लेकिन आरा का कुकृत्य शर्म का बोध करवाते हैं। जनहित सर्वोपरि।

Source: <https://www.samastipur town.com/samastipur/2026/06/nawkri-ke-bahane-nhrc-ke-member-ne-kiya-investigation/>

नौकरी के बहाने मानवाधिकार आयोग के सदस्य विकास सिंह ने की रेकी, फिर ऐसे किया पुरे गिरोह का भंडाफोड़
जून 18, 2026 Avinash Roy

समस्तीपुर : युवाओं को बंधक बनाकर चैन मार्केटिंग और ठगी के धंधे का पर्दाफाश किसी संयोग से नहीं, बल्कि सुनियोजित रेकी और खुफिया पड़ताल के बाद हुआ। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़े सदस्य विकास सिंह ने खुद नौकरी के इच्छुक युवक बनकर गिरोह के ठिकानों तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई, जिसके बाद बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया है कि विकास सिंह दो दिन पहले नौकरी की तलाश करने वाले युवक के रूप में समस्तीपुर पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होंने कालिका कॉम्प्लेक्स, मुसापुर, धरमपुर समेत अन्य ठिकानों का दौरा किया और नौकरी देने का दावा करने वाले कंपनी के संचालकों एवं सरगना से मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्हें भी नौकरी और बेहतर आय का झांसा दिया गया तथा प्रक्रिया पूरी करने के लिए 25 हजार रुपये जमा करने को कहा गया। विकास सिंह ने चालाकी से आरोपियों को भरोसे में लिया और कहा कि वह अपने बड़े भाई से पैसे मंगवाकर जल्द जमा कर देंगे। इसके बाद वह वहां से बाहर निकल आए।

इस दौरान उन्होंने परिसर में रह रहे युवक-युवतियों की संख्या, उनकी गतिविधियों और पूरे सिस्टम को करीब से देखा। उन्हें अंदेशा हुआ कि यहां बड़ी संख्या में युवाओं को संदिग्ध परिस्थितियों में रखा गया है। रेकी के बाद विकास सिंह ने पूरी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न भवनों और छात्रावासों में सैकड़ों युवक-युवतियां रह रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में युवतियां और नाबालिग भी शामिल हैं।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मिशन मुक्ति फाउंडेशन और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय स्थापित किया गया। इसके बाद बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक संयुक्त रूप से कई स्थानों पर छापेमारी की गई और 105 युवक-युवतियों एवं नाबालिगों को मुक्त कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस कार्रवाई को बिहार भर में अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू और रोजगार ठगी विरोधी अभियानों में से एक माना जा रहा है।

Source: <https://www.infonasional.com/in/kesineni-nani-nhrc-vijayawada-lockup-death>

केसिनेनी नानी ने विजयवाड़ा कस्टोडियल डेथ मामले में NHRC से शिकायत की

Benjamin Thomas

प्रकाशित Jun 18, 2026 - 18:29

पूर्व सांसद केसिनेनी नानी ने विजयवाड़ा में हुई एक कथित कस्टोडियल डेथ (लॉकअप डेथ) के मामले पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। डिशैडेली (Dishadaily) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व सांसद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराने की मांग की है।

केसिनेनी नानी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गादे साईकृष्ण के शव को गुप्त रूप से दाह-संस्कार कर दिया ताकि थर्ड-डिग्री टॉर्चर के निशान छिपाए जा सकें। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक और डीएनए साक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से साईकृष्ण की अस्थियों को कृष्णा नदी में बहा दिया गया।

पूर्व सांसद ने 'कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी' के तहत एनटीआर जिला पुलिस आयुक्त (CP) एस.वी. राजशेखर बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विजयवाड़ा में पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग को भूलकर माफियाओं का साथ दे रही है और एक "प्राइवेट सेटलमेंट सिंडिकेट" चला रही है।

नानी ने साईकृष्ण के अवैध हिरासत और कथित हत्या के इस मामले पर धारा 176(1A) के तहत तत्काल एक स्वतंत्र न्यायिक जांच शुरू करने का आग्रह किया है।

Source: <https://www.themooknayak.com/livelihood/150-dalit-families-face-livelihood-crisis-as-meerut-leather-units-sealed-nhrc-steps-in>

आजीविका

मेरठ में चर्म शोधन यूनिट्स सील होने से 150 दलित परिवारों की आजीविका पर संकट, NHRC ने कलेक्टर से मांगा ब्यौरा

आरोप है कि 13 अप्रैल को जिला प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के चर्मशोधन इकाइयों पर सील लगा दी। इस कार्रवाई से करीब 150 दलित परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है और वे आर्थिक संकट तथा भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।

The Mooknayak Published on: 19 Jun 2026, 2:22 am

मेरठ- जिले के डूंगर चर्मशोधन प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि 21 मई को मेरठ में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ शोषित क्रांति दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत के नेतृत्व में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक शिकायत पत्र सौंपा था।

शिकायत में गांव डूंगर स्थित चर्मशोधन इकाइयों को बिना पूर्व सूचना के सील किए जाने का मामला उठाया गया था। शोषित क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत ने बताया कि गांव डूंगर में दलित समाज के लोग पीढ़ियों से चर्मशोधन का कार्य करते आ रहे हैं। उनके अनुसार जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन चर्मशोधन इकाइयों का निर्माण कराया गया था और उनका अनुबंध 17 जून 2034 तक वैध है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 13 अप्रैल को जिला प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के इन चर्मशोधन इकाइयों पर सील लगा दी। आरोप है कि चर्मशोधकों को अपना कच्चा माल हटाने या उपयोग करने का भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जिसके कारण लाखों रुपये का माल खराब होकर नष्ट हो गया। शोषित क्रांति दल का दावा है कि इस कार्रवाई से करीब 150 दलित परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है और वे आर्थिक संकट तथा भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं।

शिकायत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया गया था कि मेरठ प्रशासन को निर्देशित किया जाए कि चर्मशोधन इकाइयों से सील हटाकर प्रभावित परिवारों को पुनः अपना व्यवसाय संचालित करने और आजीविका अर्जित करने की अनुमति दी जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट मेरठ से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है।

गांववालों ने की थी शिकायत, एनजीटी से बंद करने के आदेश

गांव में लंबे समय से संचालित इस चर्म शोधन कारखाने को लेकर वर्षों से प्रदूषण की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित पानी और दुर्गंध के कारण आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आसपास के गांवों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर भी ग्रामीण चिंता जताते रहे हैं।

इस मामले में पूर्व में एनजीटी द्वारा वर्ष 2013 में कारखाने को बंद करने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद कार्रवाई न होने पर हाल ही में पुनः सुनवाई के दौरान एनजीटी ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर असंतोष जताते हुए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए थे। प्रशासनिक टीम ने निरीक्षण के बाद कारखाने में कार्यरत ग्रामीणों के साथ बैठक कर स्थिति से अवगत कराया। प्रशासन ने अप्रैल माह में कारखाने को खाली करने के लिए समय दिया और उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की।

Source:

<https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/nalanda/national-human-rights-commission-sought-report-from-dgp-sp-within-four-weeks-regarding-nalanda-maghara-stampede-incident/articleshow/131838741.cms>

hindi NewsstatebiharnalandaNational Human Rights Commission Sought Report From Dgp Sp Within Four Weeks Regarding Nalanda maghara Stampede Incident

बिहार DGP और नालंदा SP से चार सप्ताह में रिपोर्ट तलब, मघड़ा भगदड़ कांड में NHRC के आदेश से पुलिस महकमे में हड़कंप
Edited by: आशुतोष कुमार पांडेय | नवभारतटाइम्स.कॉम • 18 Jun 2026, 11:25 pm IST

Nalanda News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी और नालंदा के एसपी को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। मामला जिले के मघड़ा भगदड़ मामले से जुड़ा हुआ है। इस घटना में आठ महिलाओं की मौत हो गई थी।

नालंदा: जिले के मघड़ा स्थित मां शीतला मंदिर में 31 मार्च को हुई भगदड़ की घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एवं नालंदा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने जानना चाहा है कि हादसे के बाद प्रशासन द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है।

आयोग ने मांगी रिपोर्ट

आयोग को भेजी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मां शीतला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। शिकायतकर्ता अधिवक्ता ब्रजेश कुमार का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और आठ श्रद्धालु महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। कई अन्य लोग भी घायल हुए थे।

मानवाधिकार आयोग में शिकायत

शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के समय राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों का बड़ा हिस्सा अन्यत्र व्यस्त था। इसके कारण मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती नहीं हो सकी। शिकायतकर्ता ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

शिकायतकर्ता की डिमांड

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने नोटिस में राज्य पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन से यह स्पष्ट करने को कहा है कि हादसे के कारणों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, पीड़ित परिवारों को क्या सहायता प्रदान की गई है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आयोग से मांग की है कि घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मियों की जवाबदेही तय की जाए, लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा मृतकों के आश्रितों को समुचित मुआवजा और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

क्या हुआ था?

गौरतलब है कि 31 मार्च को मां शीतला मंदिर में दर्शन-पूजन के दौरान अचानक मची भगदड़ में आठ महिलाओं की मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई थी। हादसे के उपरांत मंदिर की व्यवस्था और प्रबंधन को लेकर भी कई सवाल उठे थे। बाद में मंदिर के संचालन और प्रबंधन की

जिम्मेदारी न्यास समिति ने अपने हाथों में ले ली थी।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/bihar/nalanda/news/bihar-human-rights-commission-nalanda-temple-stampede-report-demand-138227974.html>

Hindi NewsLocalBiharNalandaNHRC Strict | Bihar DGP Nalanda SP 4 Weeks Report Demand

शीतला माता मंदिर में 8 लोगों की मौत का मामला:राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त; बिहार के DGP और नालंदा SP से मांगी रिपोर्ट नालंदा 1 घंटे पहले

नालंदा में स्थित मघड़ा शीतला माता मंदिर में बीती 31 मार्च को भगदड़ मची थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने इस हादसे को लेकर बिहार के पुलिस महानिदेशक और नालंदा के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है।

प्रशासनिक लापरवाही के कारण गई 8 जान

बता दें कि 31 मार्च को मघड़ा शीतला माता मंदिर में कुप्रबंधन और भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकांश महिलाएं थीं। इस संबंध में नालंदा निवासी दिल्ली के एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने 2 अप्रैल को आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे 18 जून को आयोग के सामने विचार के लिए रखा गया।

शिकायतकर्ता ने आयोग का ध्यान इस गंभीर प्रशासनिक विफलता की ओर खींचते हुए आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन ने मंदिर की सुरक्षा में भारी लापरवाही बरती। घटना के वक्त मंदिर परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं थी, क्योंकि पुलिस और प्रशासनिक संसाधनों को उसी समय नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में चल रहे राष्ट्रपति के दौरे की सुरक्षा में लगा दिया गया था।

NHRC ने दिए सख्त निर्देश

आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना और कानून प्रभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार इंद्रजीत कुमार के माध्यम से अधिकारियों को पत्र जारी किया। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि शिकायत की एक प्रति नालंदा SP और बिहार DGP को भेजी जाए।

दोनों वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में हुई चूक और अब तक की गई कार्रवाई पर 4 हफ्तों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। इस मामले को चार हफ्तों के बाद दोबारा आयोग के समक्ष समीक्षा के लिए पेश किया जाए।

उच्च-स्तरीय जांच और मुआवजे की मांग

शिकायतकर्ता एडवोकेट ब्रजेश सिंह ने इस पूरे मामले की एक उच्च-स्तरीय जांच कराने, लापरवाह और दोषी कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है।

Source: <https://www.etvbharat.com/amp/hi/bharat/arunachal-pradesh-minor-domestic-worker-death-youth-body-apcya-alleges-extortion-seeks-nhrc-probe-hin26061804555>

ETV Bharat / bharat

अरुणाचल में नाबालिग घरेलू सहायिका की मौत मामले में नया मोड़, NHRC से जांच की मांग

अरुणाचल प्रदेश की नाबालिग नौकरानी की मौत के महीनों बाद नए आरोप सामने आए हैं. दिल्ली से गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 5:02 PM IST

नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश में घरेलू काम करने वाली 15 साल की चकमा लड़की की मौत के मामले में नया मोड़ ले लिया है. एक युवा संगठन ने आरोप लगाया है कि मामले को रफा-दफा करने के लिए दिए गए पैसे को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सामने मूल रूप से दर्ज की गई शिकायत से जुड़े लोगों ने हड़प लिया.

अरुणाचल प्रदेश चकमा यूथ एसोसिएशन (APCYA) ने गुरुवार को एनएचआरसी से संपर्क कर उन आरोपों की जांच की मांग की है कि 11 दिसंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली (Lower Dibang Valley) जिले के रोइंग में लड़की की मौत के बाद उसके मालिक से कथित तौर पर 3 लाख रुपये लिए गए थे.

संगठन ने आयोग से यह जांच करने की अपील की है कि क्या मानवाधिकार शिकायत का गलत इस्तेमाल व्यक्तिगत फायदे के लिए किया गया था.

इस मामले ने पहले ही देश का ध्यान खींचा था, जब NHRC ने इस साल मार्च में शुरुआती जांच में हुई कमियों का हवाला देते हुए सिफारिश की थी कि किशोर की मौत के हालात की निष्पक्ष, स्वतंत्र और बच्चों के प्रति संवेदनशील जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए.

अब, APCYA का दावा है कि सोशल मीडिया पर घूम रहे एक वीडियो में पीड़ित के पिता, लक्खिमुनि चकमा (Lakkhimuni Chakma) आरोप लगा रहे हैं कि मालिक ने 3 लाख रुपये दिए, जिसमें से उनके परिवार को 1.10 लाख रुपये मिले, जबकि बाकी 1.90 लाख रुपये कथित तौर पर ऑल इंडिया चकमा स्टूडेंट्स यूनियन (AICSU) के चिकौंड चंद चकमा और एक अन्य व्यक्ति अमित चकमा ने रख लिए.

इन आरोपों से यह चिंता और बढ़ गई है कि क्या कानूनी प्रक्रिया के बाहर पैसे के लेन-देन की वजह से मृतक किशोरी को न्याय दिलाने की कोशिश में कोई बाधा आई है.

APCYA के अध्यक्ष रूप सिंह चकमा के मुताबिक, AICSU ने बाद में आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक जांच कमेटी बनाई और पीड़ित पिता के वीडियो में किए गए दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई में निष्पक्षता की कमी थी क्योंकि संगठन अपने ही सदस्यों के खिलाफ आरोपों की प्रभावी तरीके से जांच कर रहा था.

NHRC के दखल की मांग करते हुए, APCYA ने आरोप लगाया कि अगर दावे सच हैं, तो एक नाबालिग घरेलू नौकरानी की मौत से जुड़े मामले में न्याय के तरीके को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है. संगठन ने कहा कि मामले से जुड़े पैसे का कोई भी लेन-देन जांच की सत्यनिष्ठा में दखल दे सकता है और जवाबदेही को कम कर सकता है.

इसके अलावा, APCYA ने आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के उन बच्चों की कमजोरी के बारे में बड़ी चिंताएं भी जताई हैं जो घरेलू काम में लग जाते हैं. संगठन ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों को निजी तौर पर निपटाने की कोई भी कोशिश सही केस को रोक सकती है और बाल मजदूरी और शोषण के चक्र को जारी रख सकती है.

संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह साबित हो जाता है कि मानवाधिकार सिस्टम का गलत इस्तेमाल कथित तौर पर जबरन वसूली के लिए किया जा रहा है, तो इससे पीड़ितों की रक्षा करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए संस्थानों में लोगों का भरोसा कम हो सकता है.

रूप सिंह चकमा ने कहा, "APCYA ने NHRC से अनुरोध किया है कि वह अपने जांच प्रभाग के जरिये आरोपों की जांच शुरू करे और उसके नतीजों के आधार पर, इस मामले को किशोरी की मौत की पहले से अनुशंसित की गई जांच के साथ CBI को भेज दे."

DATE	CHANNEL	TIME	DETAILS	DURATION	PROGRAM	AUTHOR	PERSONALITY
18.06.2026	Gulistan News	18:00	India Raises Human Rights Concerns in Pakistan-Occupied Kashmir at UNHRC	04:49 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	ETV Telugu	19:00	<p>Hundreds of Kashmiri people living in the United Kingdom staged a major protest outside the British Parliament in London, raising concerns over alleged human rights violations in Pakistan-Occupied Kashmir (PoK).</p> <p>The protesters strongly condemned the actions of Pakistani security forces, including the army and paramilitary units, and called on the international community to take notice of the situation. Demonstrators demanded justice, protection of civil rights, and greater international attention to the challenges faced by residents of the region.</p> <p>The protest highlighted growing concerns among members of the Kashmiri diaspora regarding the political, social, and humanitarian conditions in PoK. Participants urged global institutions and human rights organizations to ensure accountability and safeguard the rights of affected communities.</p>	01:31 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	Aaj Tak	19:00	<p>5 दिन के बच्चे का सौदा! Delhi में बच्चों की तस्करी का सबसे बड़ा खुलासा</p> <p>-दिल्ली में बच्चों की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 5 मासूम बच्चों को रेस्क्यू किया है, जिनमें एक बच्चा सिर्फ 5 दिन का और दो बच्चे मात्र 27 दिन के हैं।</p> <p>इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तस्कर, बिचौलिए, खरीदार और एक अस्पताल का मालिक भी शामिल है। जांच में खुलासा हुआ कि अलग-अलग राज्यों से बच्चों को दिल्ली लाया जाता था और फिर निःसंतान (Childless) Couples को टारगेट कर उनका सौदा किया जाता था।</p>	11:06 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	Republic Bharat	10:45	<p>Child Trafficking Racket Busted in Delhi: 5 नवजात बच्चे बरामद!</p> <p>दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले एक बड़े ह्यूमन टैफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. उनके पास से पांच नवजात बच्चे बरामद हुए हैं. पुलिस ने अभी तक सिंडिकेट 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.</p>	02:26 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	Bharat Samachar	16:20	Rajasthan से Delhi तक बच्चों की खरीद-फरोख्त का खुलासा, पुलिस ने 13 आरोपियों को दबोचा -राजधानी दिल्ली में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले एक बड़े और संगठित अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने इस गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अस्पताल संचालिका, दलाल और बच्चों को खरीदने वाले परिवार भी शामिल हैं. पुलिस ने इस गिरोह के चंगुल से 5 मासूम बच्चों (जिनमें चार आदिवासी हैं) को सुरक्षित मुक्त करा लिया है. इस गिरोह का खौफनाक नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ था.	04:02 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	Punjab Keshari	13:00	Delhi Child Trafficking: दिल्ली में मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश! 13 आरोपी गिरफ्तार	03:19 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	Kalinga TV	11:10	Balianta Mob Lynching Case: Justice Yet to Be Served Despite a Month-Long Wait	03:25 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	Kalinga TV	14:00	Odisha CM Suspends IPS Officer Dayal Gangwar Over Balianta Lynching Row	03:40 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	ABP Ganga	17:00	UP : Santkabirnagar में बीच चौराहे पर युवक की गर्दन काटकर हत्या, मचा बवाल, आगजनी, भड़की हिंसा -यूपी के संतकबीरनगर में छेड़खानी के विरोध करने पर गुरुवार रात एक युवक की धारदार हथियारों से गला रेत कर हत्या कर दी गई। मामला बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे का है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। हत्या के बाद इलाके में मचा बवाल।	02:45 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	ABP News	16:20	<p>UP में गला काटकर हत्या, लोगों का गुस्सा फूटा -यूपी के संतकबीरनगर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। बीच चौराहे पर गला काटकर हत्या के बाद भारी हंगामा हुआ है। गुस्साए लोगों ने आसपास की दुकानों में आगजनी कर दी है। इलाके में तनाव है इसलिए भारी संख्या में पुलिसबल की तैनाती की गई है। आरोप है पिछले दिनों एक शादी समारोह में नासिर नाम के युवक से आनंद का झगड़ा हो गया था, आरोप है कि नासिर परिवार के किसी सदस्य के साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा था तभी आनंद ने उसे एक थप्पड़ मार दिया था, इसी का बदला लेने के लिए गुरुवार रात नासिर अपने साथियों के साथ संतकबीरनगर के बखिरा थाना इलाके में बभनी चौराहे पर पहुंचा, आरोप है कि उसने धारदार हथियार से आनंद का गला काट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, गुस्साए लोगों ने आसपास की दुकानों में आग लगा दी। वारदात के बाद से आरोपी नसीर फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिसकर्मी इलाके में तैनात है</p>	02:34 Min	News	Abc	
------------	----------	-------	---	-----------	------	-----	--

18.06.2026	Indian Express	18:00	<p>Balianta Mob Lynching: Mohan Majhi Suspends Home Dept OSD Dayal Gangwar</p> <p>In a swift and major administrative intervention following the horrific Balianta mob lynching case, Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi ordered the immediate suspension of Dayal Gangwar, Officer on Special Duty (OSD) in the Home Department. The action comes after severe public outrage over the brutal mob attack on Soumya Ranjan Swain. Acknowledging administrative gaps and lapses in handling the law-and-order situation, the Chief Minister's Office reiterated its zero-tolerance policy toward official negligence. This decisive crackdown aims to ensure accountability and deliver justice swiftly in the escalating lynching controversy.</p>	07:06 Min	Breaking News	Nishant	
18.06.2026	TV9 Bharatvarsh	14:30	<p>Bribery Allegations Against DySP</p> <p>-The Lokayukta has registered an FIR against DySP Maheshwar Gowda and Constable Basavaraju following a woman's complaint alleging a demand for money in connection with an atrocity case. The investigation is now continuing based on available evidence, including an audio recording.</p>	13:15 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	Kalinga TV	19:20	<p>Patient died due to medical negligence in Angul, family gherao hospital</p>	02:23 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	V6 News Telugu	10:20	<p>Tragedy Pregnant Women Incident at Kothagudem</p>	04:31 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	India Today	15:00	<p>Cleric Claims Hindus Are Not In Majority; Sparks Row Over Remarks On Dalits, Tribals, And Tamils</p> <p>-A major controversy has erupted following remarks made by a prominent Islamic scholar and member of the Muslim Personal Law Board at a recent conclave. The scholar asserted that Hindus do not constitute a majority in India, arguing that demographics have been misunderstood. The speaker claimed that groups such as Sikhs, Buddhists, Christians, Dalits, tribals, Tamils, and Lingayats should not be categorised as Hindus. Additionally, the cleric stated that Hindus are split into secular and fascist categories, suggesting that both segments ultimately harm their cause. These remarks have drawn sharp criticism, with representatives of Hindu organisations viewing them as an attempt to divide the majority community.</p>	04:26 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	ABP News	13:00	<p>दलित आनंद की हत्या पर सुलगा संतकबीर नगर -यूपी के संतकबीरनगर में छेड़खानी के विरोध करने पर गुरुवार रात एक युवक की धारदार हथियारों से गला रेत कर हत्या कर दी गई. मामला बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे का है. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया.</p> <p>इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया. घटना के बाद परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों हंगामा किया. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद शव को कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.</p>	02:48 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	Republic Bharat	11:15	Child Trafficking Racket Busted in Delhi: 5 नवजात बच्चे बरामद! दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले एक बड़े ह्यूमन ट्रेफिकिंग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है. उनके पास से पांच नवजात बच्चे बरामद हुए हैं. पुलिस ने अभी तक सिंडिकेट 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है.	02:36 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	Kalinga TV	17:00	How Constable Soumya Ranjan's Death Led to an NHRC Probe and an IPS Officer's Suspension	01:35 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	TV9 Telugu	11:20	Kesineni Nani Complaints To NHRC On Vijayawada Police -In a major political and legal move, senior political leader Kesineni Nani has written an official complaint letter to the National Human Rights Commission (NHRC) against the Vijayawada Police. In his letter, he raised serious concerns regarding the high-handed behavior and alleged human rights violations by the local police department. He urged the central commission to immediately intervene, initiate an independent inquiry, and take strict action against the responsible police officials to ensure justice. Watch the video for the full details of the letter, the specific allegations raised, and the ongoing political reactions in Andhra Pradesh.	01:00 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	NTV Telugu	16:20	<p>Kesineni Nani Files Complaint to NHRC Over Sai Krishna Case</p> <p>-Former MP Kesineni Srinivas lodged a complaint with National Human Rights Commission (NHRC) on the custodial death of Gade Sai Krishna and cremation of his body in a clandestine manner. The ex-MP went on to demand a judicial inquiry and suspension of the Vijayawada police commissioner.</p>	13:14 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	Thanthi TV	13:48	<p>Kesineni Nani Files Complaint with NHRC Over Vijayawada Sai Krishna Lockup Case</p> <p>-</p>	02:45 Min	Breaking News		
18.06.2026	ABN News	10:42	<p>Vijayawada Rowdy Sheeter Case: The case of the mysterious disappearance of Vijayawada rowdy-sheeter Gade Sai Krishna took a significant turn on Thursday after II additional judicial magistrate of first class court directed authorities to preserve all CCTV footage recorded at Krishnalanka police station between May 1 and June 1, 2026.</p> <p>Acting on petitions filed by Sai Krishna's mother, Gade Vijayalakshmi, the court ordered police officials to protect and safely store hard discs, DVRs, NVRs, servers and all electronic storage devices containing footage from cameras installed in and around the police station. The court also directed officials to submit certified copies of the electronic records for safe custody.</p>	03:14 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	News18 Odia	11:41	<p>Balianta Mob Lynching: Mohan Majhi Suspends OSD Dayal Gangwar</p> <p>In a swift and major administrative intervention following the horrific Balianta mob lynching case, Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi ordered the immediate suspension of Dayal Gangwar, Officer on Special Duty (OSD) in the Home Department. The action comes after severe public outrage over the brutal mob attack on Soumya Ranjan Swain. Acknowledging administrative gaps and lapses in handling the law-and-order situation, the Chief Minister's Office reiterated its zero-tolerance policy toward official negligence. This decisive crackdown aims to ensure accountability and deliver justice swiftly in the escalating lynching controversy.</p>	12:03 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	OTV News	18:00	<p>IPS Dayal Gangwar suspended, soumya case. -Dayal left the job, he used to call Soumya for massage. Big update in the Balianta Soumya death incident. Senior IPS Dayal Gangwar has been suspended. On the instructions of the Chief Minister, Dayal Gangwar, who was working as OSD in the Home Department, has been suspended. The allegations of Soumya's family had raised suspicions about the ADG. It is expected that steps will be taken as per the investigation of IPS Arun Bodra and NHRC. This is a difficult time for Soumya's family.</p>	10:45 Min	Breaking News	Abc	

18.06.2026	OTV	10:30	<p>CM Orders Suspension of ADG Dayal Gangwar Over Constable Deployment Allegations</p> <p>-Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has directed the suspension of ADG Dayal Gangwar following a confidential report submitted by the Director General of Police to the Home Department based on a Crime Branch inquiry. The report alleges that Gangwar had engaged eight constables, including deceased GRP constable Soumyaranjan Swain, in personal and household duties at his residence.</p>	07:18 Min	Breaking News	Abc	
18.06.2026	OTV	14:00	<p>Gangwar Suspended Amid Soumya Murder Case Controversy</p> <p>-Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has directed the suspension of ADG Dayal Gangwar following a confidential report submitted by the Director General of Police to the Home Department based on a Crime Branch inquiry. The report alleges that Gangwar had engaged eight constables, including deceased GRP constable Soumyaranjan Swain, in personal and household duties at his residence.</p>	10:56 Min	Breaking News	Abc	

